को उपहार/दान में देने के लिए तथा विदेश स्थित हमारे मिशनों में एक मानक पुस्तकालय बनाने के लिए भारतीय इतिहास, संस्कृति साहित्य, धर्म आदि पर विदेश स्थित अपने मिशनों को पुस्तकें भेजती रहती है।

मंत्रालय ने पोर्ट आफ स्पेन, पोर्ट लुई, सुवा, जॉर्ज टाउन, लंदन और पारामारिबो में हिन्दी अधिकारियों और काठमाण्डू में हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति भी की है, जो हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार-प्रसार का कार्य करते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् बहुत से देशों में सांस्कृतिक केन्द्र चला रही है। भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए सामान्यतया विदेश स्थित हमारे मिशनों में सूचना और सांस्कृतिक खण्ड हैं।

Sale of supercomputers to India by U. S.

@1657. SHRI CHITTA BASU:
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether U. S. has since taken any final decision to supply super computers to India;

(b) if so, what is the nature of the decision;

(c) whether any conditions are attached; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Government have received no communication regarding the final decision of the U.S. Goverment to suppl suprocomputers to India.

(b) to (d) Do not arise.

@Previously Unstarred Question 1154 transfered from the 5th March 1987.

राजभाषा समिति

1658. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्री जी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, और यदि हां, तो वह इस समिति के कार्यालय में कितनी बार गए हैं;

(ख) क्या उन्होंने कभी इस समिति की तीन उप-समितियों में से किसी एक की भी बैठक में भाग लिया है और क्या उन्होंने कभी समिति के निरीक्षण कार्य की समीक्षा की है;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने यहां हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन करने और वर्ष में उनकी कम से कम चार बैठकें बुलाने के बारे में पत्र लिखकर अनुरोध किया है; यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्री अपने मंत्रालय के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें राजभाषा के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि कोई भी मंत्री या सचिव राजभाषा को गंभीरता से नहीं लेता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, गृह मंत्री जी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ समय में उनका समिति के कार्यालय में आने का अवसर नहीं आया। तथापि, समिति की अब तक हुई सभी बैठकों की उन्होंने अध्यक्षता की है।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति की कार्यविधि और कार्य संचालन की नियमावली के अनुसार अध्यक्ष द्वारा उप-समितियों के कार्यकलाप में भाग लेना अपेक्षित नहीं है। इन उप-समितियों की निरीक्षण

रिपोर्टों को सचिवालय द्वारा संकलित करके समिति को उसकी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार जब समिति द्वारा समय-समय पर अपनी बैठकों में निरीक्षणों की प्रगति की समीक्षा होती है तो अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी हो जाती है।

(ग) 1985 में बहुत से मंत्रालयों के स्वरूप और नामों में परिवर्तन होने के कारण उनकी हिन्दी सलाहकार समितियों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो गई। अतः सभी मंत्रालयों से सामान्य कार्यालय-पद्धति के अनुसार अपनी अपनी समितियों के स्वरूप की समीक्षा करने, अपेक्षित परिवर्तन शीघ्र करने और उनकी नियमित बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया। जिन मंत्रालयों ने पुनर्गठन/परिवर्तन करने में अनावश्यक देरी की उन्हें मंत्री स्तर पर स्मरण कराया गया।

(घ) जी नहीं।

U.N. sponsored study on forests.

1659. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government"s attention has been drawn to a recent UN sponsored study according to which 27 million acres of forests are destroyed annually;

(b) if so, what is the acreage under forests destroyed annually in India; and

(c) what steps are being taken to check such deforestation?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BHAJAN LAL): (a) Yes, Sir.

(b) According to the National Remote Sensing Agency, the annual rate of deforestation in India during 1972-75 to 1980-82 was 1.3 million hectares per annum.

(c) The following steps have been taken by the Government to check deforestation:—

1. Enactment and enforcement of the Forest (Conservation) Act, 1980.

2. Guidelines have been issued to the state governments to:—

(i) avoid clear felling of natural forests for raising plantations as far as possible. Where such fellings are unavoidable due to restoration of crop or other silvicultural considerations, it should be restricted to areas not-exceeding 10 ha. in the hills and 20 ha. in the plains. In no case good natural forests should be clear-felled in preferenc to poorly stocked natural forests.

(ii) ban all fellings above an altitude of 1000 meters atleast for some years.

(iii) to earmark 4 per cent of the geographical area as protection areas, like wildlife sanctuaries, National parks, Biosphere Reserves, Preservation Plots, etc.

(iv) prefer raising of mixed species of indigenous origin to monoculture. The indgenous species should receive precedence over exotics.

3. The National Wastelands Development Board has been set up with the object of bringing 5 million hectares of land every year under fuelwood and fodder plantation.

Pending industrial disputes

1660. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many industrial disputes are persently pending in various Tribunals and Labour Courts in Delhi to be disposed of, Tribunal-wise/Court-wise;

(b) how many of them are between public sector undertakings and their workers| Unions, Public sector-wise;

(c) how many such disputes are pending for more than five years, public sector-wise|tribunal-wise|court-wise;